

लेकिन आठ दिसम्बर 2023 तक
आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है।

केंद्रीय मंत्री नित्यानन्द राय ने इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव रखा। इससे पहले भाजपा संसदीय ने हांगमे के बीच अपनी बात रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में आदिवासी, एसपी-एसटी महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की है। तेज हांगमे 30 और नारेबाजी के बीच राज्यसभा के सभापति ने पेश किए गए बिल पर संसदीय से उनका मत मांगा। ध्वनि मत से राज्यसभा में सोमवार को बिल पारित कर दिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले लोकसभा विधेयक पारित कर चुकी है। लोकसभा में दो व्यक्तियों के जबरन घुसने के मुद्दे पर सभापति ने राज्यसभा में बताया कि यह सामुहिक चिंता का विषय है। एक उच्च स्तरीय कमेटी मामले की जांच कर रही है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि भवित्व में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। हालांकि, विषयक संसद सभापति के बयान से संतुष्ट नहीं हुए और गृह मंत्री के बयान की मांग करते रहे। विषयक लगातार 'गृहमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ', 'गृहमंत्री जवाब दो, जवाब दो' के नारे लगता रहा। विषयक द्वारा किए जा रहे हांगमे से नाराज सभापति ने सदन में इस प्रकार के व्यवहार को निदनीय कराया दिया। हांगमा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने हांगमे पर विराम लगाने के लिए नेता प्रतिष्ठक मरिलकार्जुन खड़गे को मुलाकात और चर्चा के लिए अपने चेंबर में आर्मित किया।

अधिकारी सॉलिसिटर जनरल
(एसजी) चेन शमा ने केंद्र
सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
अदालत को सुचित किया कि
विधेयक एक अधिनियम बन गया
है। यह जनगणना के बाद की एक
कावयद है। इसे अधिनियम के
अंतर्गत शामिल किया गया है। इस
पर संसद में बहस हो चुकी है... यह
याचिका महज प्रबाल के लिए दायर
की गई है।" याचिकाकर्ता ने
अधिनियम या विधेयक की वैधता
को चुनौती न देने हुए महिला
आरक्षण को समयबद्ध तरीके से
लागू करने की मांग की।" मैं
अधिनियम या विधेयक को चुनौती
नहीं दे रहा हूं... भारत के इतिहास
में पहली बार संसद ने सर्वसमानता
से विधेयक पारित किया है। 75
साल से प्रतिनिधित्व नहीं मिला, वे

अपें और कहे कि हम इसे
समयबद्ध तरीके से कर सकते हैं।
मैं किसी भी चीज को चुनौती नहीं
दे रहा हूं। मैं सिफर यह कांशश
कर रहा हूं कि इसे समयबद्ध तरीके
से किया जा सके। अन्यथा ऐसा
होने वाला नहीं है। अदालत ने
महिला आरक्षण से पहले परिसीमन
की संसदीय शर्त पर गौर किया
और प्रावधान की वैधता को चुनौती
देने का सुझाव दिया। इसने संवैच्च
न्यायालय में चल रहे मामले और
याचिकाकर्ता को या तो इसे रद्द
करने या ठोस आधार पेश करने
की आवश्यकता पूरी जौर दिया।
जनहित याचिका वापस लेने के
साथ, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
मनमोहन और न्यायमूर्ति मिसी
पुष्करण ने याचिकाकर्ता, वकील
याचिका एम.जी. को सुप्रीम कोर्ट
जाने की स्वतंत्रता दी, जहाँ इसी
लाइवट है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम
प्रसाद ने पिछले सप्ताह इसी मामले
पर विचार करने से इनकार कर
दिया था और कहा था कि प्रार्थनाएं
एक जनहित याचिका के समान हैं
और याचिकाकर्ता को याचिका
वापस लेने और एक नई जनहित
याचिका दायर करने का सुझाव
दिया था।